नाबार्ड

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

किसान : ई-पैक्स की प्रेरक शक्ति

किसान, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं.
ई-पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस रीढ़ को डिजिटली सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन और परिचालन में पारदर्शिता को बल मिलेगा

ग्रामीण सहकारी समितियों में डिजिटल क्रांति में शामिल हों।
अपनी सहकारी संस्था को सशक्त बनाइये।
अपने भविष्य को सशक्त बनाइये।

/nabardonline

ई-पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान-केंद्रित डिजिटलीकरण

प्राथमिक लाभार्थी
किसान महत्वपूर्ण हितधारक हैं, जिन्हें ऋण, बचत और सहकारी सेवाएँ ई-पैक्स के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं

शासन को मजबूत करना
पैक्स की मतदाता सूची का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सक्षम बनी है तथा सहकारी कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
आधार सक्षम ई-केवाईसी, सेवाओं को सुलभ बना रहे हैं।

क्षमता निर्माण
किसानों को डिजिटल रूप से साक्षर, आत्मविश्वासी और भविष्य के लिए तैयार होने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

किसानों के लिए प्रमुख लाभ

त्वरित ऋण प्रसंस्करण
फसल एवं सावधि ऋणों के लिए त्वरित अनुमोदन एवं संवितरण।

वास्तविक समय पहुंच
किसी भी समय शेष राशि, पुनर्भुगतान कार्यक्रम और लेनदेन इतिहास की जांच करें।

पारदर्शिता
स्पष्ट विवरण और डिजिटल रिकॉर्ड।

स्थानीयकृत समर्थन
उपयोग में आसानी के लिए १४ भाषाओं में उपलब्ध।

स्मार्ट अलर्ट
नियत तिथियों, अनुमोदनों और घोषणाओं के लिए सूचनाएं।

ग्रामीण सहकारी समितियों में डिजिटल क्रांति में शामिल हों।
अपनी सहकारी संस्था को सशक्त बनाइये।
अपने भविष्य को सशक्त बनाइये।